पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक आवेदन (डी. बी.) संख्या- 206

2013 के थाना कांड संख्या- 137 से उत्पन्न थाना- डुमराँव, जिला- बक्सर

==========

सत्यमानु कुमार सिंह, पुरुष, आयु लगभग 36 वर्ष, स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह का पुत्र, ग्राम का निवासी-हरिजी का हाटा, डुमरांव, पुलिस स्टेशन-डुमरांव, जिला-बक्सर।

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य ..... प्रत्यार्थी

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

: श्री पारिजात सौरव, अधिवक्ता

: श्री विपिन कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के वकील : सुश्री शशि बाला वर्मा, ए. पी. पी.

==========

भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 376 (2)(एफ) और 377 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 धारा 4 डॉक्टर ने आरोपी की जाँच की और पाया कि आरोपी मानसिक और शारीरिक रुप से सामान्य था और यौन क्रिया करने में सक्षम था, लेकिन यह अपने आप में आरोपित अपराधें के लिए दोषसद्धि नहीं कर सकता - हलाँकि पीड़िता का बयान धारा 164 सी.आर.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया था, जिसका उपयोग पुष्टि या विरोधाभास के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता - पीड़िता खुद ही मुकर गई और उसने अभियोजना पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, चिकित्सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से पुष्ट नहीं हुआ, इसलिए, संदेह का लाभ अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए। निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि आरोपी ने केवल 164 के बयान पर भरोसा करके पीड़िता के साथ बलात्कार किया, कायम नहीं रखा जा सकता - दोषसिद्धि और सजा रद्द की जाती है।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय श्री चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती

मौखिक निर्णय

(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ती श्रीमति गुन्नु अनुपमा चक्रवर्ती के अनुसार

तिथीः- 08.11.2023

यह अपील अपर जिला और सत्र न्यायाधीश VI-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, बक्सर द्वारा 2015 का पॉक्सो मामला संख्या 18 (जो डुमरांव पी. एस. 2013 के मामले संख्या 137 से उत्पन्न हुआ) में पारित दोषी ठहराए जाने के फैसले और सजा के आदेश 07.02.2022 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ), 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हैः

2022 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 206				
अपीलार्थी का नाम	धारा के तहत दोषी ठहराया गया	सजा		
		अर्थदण्ड (रु०)	कारावास जुर्माना (रु.)	जुर्माना न अदा करने पर
सत्यमानु कुमार सिंह	376(2)(च) आई. पी. सी.	आजीवन कारावास	1,00,000/-	एस. आई. 1 वर्ष के लिए
	377 आई. पी. सी.	आर. आई. 10 साल के लिए।	50,000/-	एस. आई. 6 महीने के लिए
	पॉक्सो अधिनियम की धारा 4	20 वर्षों के लिए आर. आई.	1,00,000/-	एस. आई. 1 वर्ष के लिए

2. सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

3. हम इस मामले में पीड़िता और अभियोजन पक्ष के गवाहों के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामला पॉक्सो अधिनियम के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत है। बाद में पीड़िता का बयान 164 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत 15.07.2013 को दर्ज किया गया।

4. हमने श्री बिंध्याचल सिंह को सुना है, जो अपीलार्थी के लिए वरिष्ठ वकील हैं और बिहार राज्य के लिए विद्वान लोक अभियोजक हैं।

5. आपराधिक कानून पी.डब्ल्यू.-7 द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर शुरू किया गया था, जो पीड़िता लड़की का पिता है। लिखित शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि 12.07.2013 को, लगभग 07:30 बजे संध्या अपीलार्थी जो उनके घर के बगल में रहता है, अपनी लगभग 7 साल की बेटी/पीड़िता को अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता रोते हुए घर लौटी और अपनी माँ अर्थात पी.डब्ल्यू.1 को घटना के बारे में बताया। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू.1, जिसे मुखबिर यानी पी.डब्ल्यू.-7 कहा जाता है, ने उसे उस घटना के बारे में सूचित किया जिसने डुमरांव पुलिस स्टेशन के पुलिस/प्रभारी को लिखित जानकारी दी।

6. उक्त लिखित आवेदन के आधार पर, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय कथित अपराध के लिए 2013 की अपराध संख्या 137 दिनांक 12.07.2013 के माध्यम से मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, पीड़िता को उसी तारीख को आधी रात को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था। फिर से, डॉक्टरों की एक टीम द्वारा 17.07.2013 को पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की गई। पुलिस ने आ.प.सं. की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं और जांच पूरी करने पर आई. पी. सी. की धारा 376 और 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। निचली अदालत ने 26.07.2013 को उक्त अपराधों के लिए संज्ञान लिया और बाद में मामले की संचिका सत्र न्यायालय को सौंप दी गई। सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी के

खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) और धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 31.10.2013 को आरोप तय किए। इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप 25.01.2016 को जोड़ा गया था। अपीलार्थी ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

7. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी को 2014 को आपराधिक विविध संख्या- 853 में दिनांकित विशेषाधिकार जमानत आदेश दिया गया था। अपीलार्थी 12.07.2013 से 01.02.2014 तक हिरासत में रहा, उसके बाद वह जमानत पर था। इसके अलावा, अपीलार्थी ने 14.12.2021 को आत्मसमर्पण कर दिया और फिर से 31.01.2022 को जमानत दे दी गई और 07.02.2022 को उसे हिरासत में ले लिया गया और तब से वह जेल में है।

8. अपीलार्थी के खिलाफ मामला साबित करने के लिए उचित संदेह से परे, अभियोजन पक्ष ने तेरह गवाहों यानी पीडब्लू 1-पीड़िता की माँ, पीडब्लू-2.पीड़िता की मातृ चाची, पीडब्लू 3-पीड़िता की मातृ दादी, पीडब्लू-4-पीड़िता की चाची, पीडब्लू5 और 6 पंच गवाह, पीडब्लू 7-पीड़िता के पिता, पीडब्लू 8-खुद पीड़ित, पीडब्लू 9-पीड़िता के दादा, पीडब्लू। 10 और 11-डॉक्टर, पीडब्लू 12-जांच अधिकारी और पीडब्लू 13-न्यायिक अधिकारी।

9. अभियोजन पक्ष के गवाह के मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर दस्तावेजी-साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, अर्थात् प्रदर्श 1 से 15 अर्थात् प्रदर्श-1 जब्ती सूची पर रविंद्र सिंह के हस्ताक्षर, प्रदर्श-1/1 जब्ती-सूची पर उपेंद्र राय के हस्ताक्षर, प्रदर्श-2 सूचक की लिखित याचिका, प्रदर्श-1/2 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान पर पीड़िता के हस्ताक्षर प्रदर्श-3 पीड़िता की दिनांक 13/07/2013 की मेडिकल रिपोर्ट/प्रतिवेदन, प्रदर्श-4 मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए पुलिस की याचिका पर डॉक्टर का समर्थन प्रदर्श-5 पीड़िता की दिनांक 17/07/2013 की मेडिकल प्रतिवेदन, प्रदर्श 6 दिनांक 17.07.2013 के मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए पुलिस की याचिका पर डॉक्टर का समर्थन,

प्रदर्श-7- आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट/प्रतिवेदन, प्रदर्श 1/3- मेडिकल रिपोर्ट/प्रतिवेदन पर आरोपी का हस्ताक्षर, प्रदर्श 8- जब्ती, सूची, प्रदर्श 9 और 9/2-पीड़ित की मेडिकल जाँच के लिए अनुरोध पत्र, प्रदर्श 10 - आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने की लिए अनुरेध पत्र, प्रदर्श 11- औपचारिक एफ.आई.आर/ प्रथम सूचना प्रतिवेदन, प्रदर्श 1/4 164 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर प्रदर्श 12-164 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के लिए समर्थन पत्र पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी का समर्थन प्रदर्श 13 - आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान, प्रदर्श 14-एप.एस.एल रिपोर्ट/प्रतिवेदन और प्रदर्श 15 -एफ एस एल रिपोर्ट/प्रतिवेदन।

10. अभियुक्त/अपीलार्थी से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के दोषपूर्ण साक्ष्य से इनकार किया और कोई बचाव साक्ष्य नहीं दिया। अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री पर विचार करते हुए, निचली अदालत ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ), 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

11. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह विशिष्ट तर्क है कि पीड़िता (पी.डब्लू-2) और पीड़िता के पिता (पी.डब्लू-7) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और इसके बावजूद निचली अदालत ने अपीलार्थी को पटना आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी ठहराया। यह आगे तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष का मामला चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य एक दूसरे के साथ विरोधाभासी हैं। इसके अलावा, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पी.डब्ल्यू.-7 और 9 पीड़िता के पिता और दादा हैं, जिन्होंने विशेष रूप से कहा कि अन्य गवाह अपराध की तारीख पर मौजूद नहीं थे और इसलिए, अन्य गवाहों की उपस्थिति स्वयं संदिग्ध है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4

के तहत और आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) और 377 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि गलत और विकृत है और इसलिए, निचली अदालत के फैसले और सजा को रद्द करने का अनुरोध किया।

12. अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ***आर. शाजी बनाम केरल राज्य*** के मामले में ***(2013) 14 एस. सी. सी. 266*** में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय प्रभुत्व ने कहा हैः

> *"**26.** शपथ के तहत अदालत में दिए गए साक्ष्य की बहुत पवित्रता होती है, यही कारण है कि इसे मूल साक्ष्य कहा जाता है। धारा 161 सी. आर. पी. सी. के तहत बयानों का उपयोग केवल विरोधाभास के उद्देश्य से किया जा सकता है और धारा 164 सी. आर. पी. सी. के तहत बयानों का उपयोग पुष्टि और विरोधाभास दोनों के लिए किया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां दंडाधिकारी को धारा 164 सी. आर. पी. सी. के तहत बयान दर्ज करने का कर्तव्य निभाना है, वह उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बाध्य है जो गवाह प्रकट करना चाहता है, एक गवाह के रूप में जो एक अनपढ़, देहाती ग्रामीण हो सकता है कि उसे उस उद्देश्य के बारे में पता न हो जिसके लिए उसे लाया गया है, और दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 164 के तहत अपने बयानों में उसे क्या खुलासा करना चाहिए। इसलिए, दंडाधिकारी को गवाह से व्याख्यात्मक प्रश्न पूछने चाहिए और उक्त मामले के संबंध में सभी संभावित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।*
>
> ***29.** जाँच के दौरान, पुलिस अधिकारी कभी-कभी महसूस कर सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक गवाह का बयान दर्ज करना समीचीन है। यह आमतौर पर तब होता है जब किसी अपराध के गवाह स्पष्ट रूप से आरोपी से*

जुड़े होते हैं, या जहां आरोपी बहुत प्रभावशाली होता है, जिसके कारण गवाह प्रभावित हो सकते हैं। (मामंद बनाम सम्राट [(1946) 59 एल. डब्ल्यू. 138:ए. आई. आर. 1946 पी. सी. 45], भुबोनी साहू बनाम आर. [(1948-49) 76 आई. ए. 147:ए. आई. आर. 1949 पी. सी. 257], राम चरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। [ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1270:1968 क्री एल. जे. 1473] और धनबल बनाम टी. एन. राज्य [(1980) 2 एस. सी. सी. 84:1980 एससीसी (सीआरआई) 340:ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 628])"

13. दूसरी ओर, बिहार राज्य के लिए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश में कोई त्रुटियां और अनियमितता नहीं है और विशेष रूप से तर्क दिया कि पीड़िता के 164 बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है, इसलिए, फैसले की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

14. हमने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी अधिवक्ताओं पर विचारपूर्वक विचार करते हुए निचली अदालत के फैसले और अभिलेख का भी अध्ययन किया है।

15. इस अपील में निर्धारण का मुद्दा यह है कि क्या अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) और 377 और पॉक्सो की धारा 4 के तहत और क्या निचली अदालत ने उक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी को सही तरीके से दोषी ठहराया है।

16. साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसे इस न्यायालय द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के मौखिक साक्ष्य का समर्थन करता है।

17. जैसा कि उपरोक्त कहा गया है सूचना देने वाला पीड़िता लड़की का पिता है जिसकी जाँच पी.डब्ल्यू-7 के रूप में की गई थी। पी.डब्ल्यू-1 पीड़िता की माँ है।

पी.डब्ल्यू-1 द्वारा यह गवाही दी गई है कि पीड़िता के साथ 06 बजे शाम 12.07.2013 को गुदा बलात्कार किया गया थाः लेकिन प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू-1 ने स्वीकार किया कि उसने निरीक्षक को सूचित किया कि उसने पीड़िता के जननांगों से खून बहते देखा। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू-1 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया, उसकी पैंट उतार दी और पीछे से उसके साथ बलात्कार किया और पीड़िता पैर लंगड़ाकर घर आई। उसने आगे गवाही दी कि उसने पीड़िता की पैंट उतार दी, और उस पर खून और वीर्य देखा। जिरह में, यह विशेष रूप से पी.डब्ल्यू-1 द्वारा स्वीकार किया गया है कि पीड़िता के पैर पर कोई खून नहीं था और यह भी स्वीकार किया कि उसने निरीक्षक को बताया कि जब उसने पीड़िता की पैंट निकाली, तो उसने पीड़िता के जननांगों से खून निकलते देखा और बाद में, पीड़िता उसी पैंट/अंडरवियर के साथ पुलिस स्टेशन गई।

18. पीडब्लू 2 और 3 क्रमशः पीड़िता की चाची और दादी हैं। पी.डब्ल्यू-2 ने गवाही दी कि 12.07.2013 को 06:30 बजे शाम और 07:00 बजे शाम के बीच, उसने पीड़िता को रोते हुए और आरोपी के घर से बाहर निकलते देखा। इसके अलावा, जब उसने पूछा कि क्या हुआ है, तो पीड़िता ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन वह पीड़िता के पीछे उसके घर तक गई, जहाँ पीड़िता ने पी.डब्ल्यू-1 को घटना के बारे में सूचित किया। उसने यह भी गवाही दी कि पी.डब्ल्यू.-1 ने पीड़िता की पैंट को हटा दिया, फिर उसने पीड़िता लड़की के जननांगों में मौजूद रक्त के दाग और शुक्राणुओं को देखा।

19. पी.डब्ल्यू-3 जो पीड़िता की दादी हैं, ने घटना की तारीख को पीड़िता की पैंटी/पैंट पर खून और वीर्य के अवलोकन और पीड़िता लड़की की गुदा पर काफी सूजन के बारे में भी गवाही दी। पी.डब्ल्यू-3 के साक्ष्य से केवल यह पता चलता है कि आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और बाद में पीडब्ल्यू-1 और 2 के माध्यम से घटना के बारे में पता चला।

20. पी.डब्ल्यू-4 पीड़िता की चाची है। उसके साक्ष्य से पता चलता है कि उसने घटना की तारीख को पी.डब्ल्यू-1 के घर पर महिलाओं को चिल्लाते और रोते हुए देखा और उसने पीड़िता के गुप्तांगों पर भी देखा, जिसमें खून से लथपथ वीर्य और पीड़िता की पीठ पर खरोंच और सूजन थी।

21. पी. डब्ल्यू. 5 और 6 दिनांकित 12.07.2013 की जब्ती सूची के पंच गवाह हैं। यह जब्ती उस चादर के संबंध में है जो आरोपी के घर में पाई गई थी। वे दोनों मुकर गए और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

22. जैसा कि उपरोक्त कहा गया है, पीडब्लू 7 पीड़िता का पिता है। उसके साक्ष्य से पता चलता है कि वह घटना के समय मौजूद नहीं था और उसे अपनी पत्नी के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चला। उन्होंने आगे गवाही दी कि लिखित आवेदन उनकी बहन द्वारा लिखा गया था, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे जो कि प्रदर्श-पी2 है। जिरह में पी. डब्ल्यू. 7 द्वारा विशेष रूप से यह स्वीकार किया गया है कि कथित घटना के बाद उन्होंने अपनी बेटी से बात नहीं की थी।

23. पीडब्लू 8 पीड़िता लड़की है। सत्र न्यायाधीश ने शुरू में पीड़िता से सरल प्रश्न पूछे हैं ताकि गवाह की तर्कसंगत उत्तर देने की क्षमता का पता लगाया जा सके और यह संतुष्ट होने के बाद कि गवाह समझने और उत्तर देने में सक्षम था, वह साक्ष्य दर्ज करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन पीडब्लू 8 ने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया।

24. पीडब्लू 9 पीड़िता के दादा हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। लेकिन, उसके साक्ष्य से पता चलता है कि घटना की तारीख को वह रांची में अपनी पत्नी और अन्य बेटियों के साथ थे। इसलिए, अपराध स्थल पर पीडब्लू 2 और 3 की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है।

25. पी. डब्ल्यू. 10 वह डॉक्टर है जिसने घटना की तारीख से तीन दिनों के अंतराल के भीतर दो बार गवाहों की जांच की। शुरू में उन्होंने आधी रात को 12.07.2013 को पीड़िता (पीडब्लू 8) की जांच की। उसे पीड़िता की योनि और योनि की दीवार पर कोई चोट नहीं मिली। यह पीडब्लू 10 द्वारा कहा गया है-पीडब्लू 8 की योनि ने उंगली की नोक को स्वीकार नहीं किया। हालाँकि, पी.डब्ल्यू-10 ने रेडियोलॉजिकल निष्कर्षों के अनुसार पीड़िता की आयु सात से आठ (7-8) वर्ष के बीच निर्धारित की और राय दी कि पीड़िता को बलात्कार नहीं किया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि पीडब्लू 8 शत्रुतापूर्ण हो गया। हालाँकि, चिकित्सा साक्ष्य भी किसी भी तरह से अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते हैं।

26. इसके अलावा पीड़िता लड़की/पीडब्लू-8 का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 दर्ज करने के बाद तीन दिनों के बाद पीड़िता की चिकित्सकीय जांच फिर से की गई। पीडब्लू 10 ने पीड़िता की गुदा की जांच की और कहा कि पीड़िता लड़की की गुदा पर कोई चोट या खरोंच का निशान नहीं मिला है और आगे गुदा प्रवेश का कोई संकेत नहीं है।

27. पीडब्लू 1 के साक्ष्य के अनुसार एक गुदा बलात्कार है लेकिन जहां तक पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य का संबंध है, जननांग/योनि का बलात्कार है। पी. डब्ल्यू. 1 का साक्ष्य पी. डब्ल्यू. 2 और 3 के साक्ष्य के साथ असंगत है।

28. दूसरी ओर, पीडब्लू 4 का साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ विरोधाभासी है क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से कहा कि पीड़िता की पीठ पर खरोंच थी और पीड़िता की गुदा सूज गई थी।

29. इसके अलावा, पीडब्लू 11, डॉक्टर ने 13.07.2013 को आरोपी की जांच की। जाँच पर, उसने पाया कि आरोपी मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य था और

यह भी गवाही दी कि आरोपी के शरीर पर कोई चोट नहीं थी और वह यौन कृत्य करने में सक्षम है।

30. हालाँकि, अभियुक्त यौन क्रिया करने में सक्षम है, लेकिन यह स्वयं आरोपित अपराधों के लिए अपराध साबित नहीं कर सकता है। चिकित्सीय साक्ष्य के साथ पुष्ट ठोस मौखिक साक्ष्य के अभाव में, यह माना जा सकता है कि अपीलार्थी को आरोपित अपराधों में निर्दोष माना जाएगा। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान का उपयोग पुष्टि या विरोधाभास के लिए किया जा सकता है, लेकिन दोषसिद्धि के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

31. पीडब्लू 12 जाँच अधिकारी है और पीडब्लू 13 न्यायिक अधिकारी है, जिसने पीड़िता का 164 आपराधिक प्रक्रिया संहिता बयान दर्ज किया।

32. पूरे साक्ष्य के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। पीड़िता स्वयं मुकर गई है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा, अन्य गवाहों की उपस्थिति संदिग्ध है। पी. डब्ल्यू. 7 पीड़िता के पिता ने स्वयं कहा कि उन्होंने कथित घटना के बाद पीड़िता से बात नहीं की। इसके अलावा, चिकित्सा साक्ष्य की मौखिक साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है, इसलिए, संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए। इसलिए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि आरोपी ने पीड़िता लड़की पर यौन हमला/बलात्कार किया है या तो उसके जननांगों पर या 7 साल से कम उम्र की पीड़िता पर गुदा प्रवेश किया है। इसके अलावा, आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत सजा को आकर्षित करने के लिए चिकित्सा साक्ष्य अप्राकृतिक अपराध के बारे में खुलासा नहीं करते हैं।

33. अभिलेख पर यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) या 377 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।

34. इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 को लागू करने वाली धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भी कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि आरोपी ने केवल 164 के बयान पर भरोसा करते हुए पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ), आई. पी. सी. की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और निर्णय और दोषसिद्धि और सजा का आदेश क्रमशः 07.02.2022 और 09.02.2022 को दरकिनार कर दिया जाता है। अभिलेख से पता चलता है कि अपीलार्थी 07.02.2022 के बाद से जेल में है, इसलिए, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

35. अपीलार्थी को जमानत बांड और प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

(चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति)

(गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति)

शानू/अमित

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक,

कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।